रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :–

1989	—	1979 व्यक्ति
1990	—	1732 व्यक्ति
1991	—	1825 व्यक्ति

1992 से संबंधित सूचना निम्न विरचनाओं से एकत्रित की जा रही है।

(ख) अनुकम्पा-आधार पर नियुक्तियां करने के लिए प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर सभी सुसंगत पहलुओं और आवेदनों के औचित्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

4001. [*Transferred to the 19th August*, 1992.]

Manufacture of submarines

4002. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in the 'Sunday Observer', New Delhi of 2nd August, 1992 under the caption "Delay on new sub alarms in Navy";

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) what are the reasons for the delay in manufacturing our own sub-marines for Indian Navy in the East Yard of Bombay's Mazagon Dock;

(d) the extent to which the delay in manufacturing submarines would upset the Silver Jubilee Year of the Navy's Submarine arm which was started in 1967 and affect the interest of defence preparedness and capabilities; and

(e) what steps Government propose to take for the early manufacture of submarines and what is Government's programme in this regard?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) Yes, Sir.

(b) As per the agreement of Government of India with M|s. HDW of Germany, two SSK type submarines were built in German shipyard and another two have been manufactured with HDW collaboration in East Yard of MDL, Bombay.

(c) The main reason is that manufacture of a Submarine is a highly complicated venture which was attempted for the first time in the country.

(d) and (e) The modernisation of the Indian Navy is being carried out in terms of the Perspective Plan which has been drawn up for this purpose. The decision to acquire new equipment is taken on the basis of this Perspective Plan, as well as an assessment of the geo-political scenario, threat perception and the availability of funds with the Navy. It is ensured that the Navy remains a balanced force capable of meeting any exigency that may arise.

रक्षा प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

4003. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुल्लु जिले में फाटी बुसशा, फाटी पलचान और कोठी पलचान के स्थानीय लोगों की भूमि जो 1988 में कब्जे में ली गई थी, को अधिगृहीत कर लिया गया है और भूस्वामियों को उसका मुआवजा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मुआवजा कब दिया गया और भूमि का अधिग्रहण कब किया गया ;

(ग) क्या भूमि को कब्जे में लेने और अधिग्रहण की अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख के बीच की अवधि के लिए भी स्थानीय किसानों/भू-स्वामियों को मुआवजा दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कितना; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पट्टी पालचन और बाखा पालचन सहित कुछ गांवों में निजी भूमि के अधिग्रहण और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को रक्षा विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में सरकार की स्वीकृति 26.2.1991 को जारी की गई थी। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है।

भू-स्वामियों को सेना द्वारा भूमि को कब्जे में लिए जाने की तारीख अर्थात् 1.7.1988 से 31.12.1991 तक, 64,417 रुपये प्रति वर्ष की दर से किराए के रूप में कुल 2,25,459 रुपये के मुआवजा की अदायगी कर दी गई है।

किराए के रूप में भूमि के मुआवजे की अदायगी तब तक की जाती रहेगी जब तक कि भूमि का अधिग्रहण औपचारिक रूप से नहीं कर लिया जाता। सरकार ने कोठी पालचन में कोई भूमि अधिगृहीत नहीं की है।

अमरीका के साथ सैनिक समझौता

4004. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अमरीका के साथ कोई सैनिक समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सैनिक समझौता किये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Private enterprises to manufacture defence materials

4005. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are planning to promote private enterprises in the manufacturing of materials needed for defence; and

(b) whether such proposal would include the participation of multinational companies ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) In order to achieve a high degree of self reliance, Government's policy is to make optimum use of the national industrial infrastructure. Pursuant to this policy, capacities available in the civil sector both in the private and the non-defence public sectors are being utilised for production of defence stores.

(b) There is no bar to utilise the capacity available with the Indian Units of multinational companies so far as production of non-lethal|non-sentitive defence stores is concerned.

Training to forcign airmen

4006. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether any training is being provided by Indian Airforce to the airmen of various foreign countries;